न्यायमूर्ति एस.एस. सरोन और एस.पी.बनगढ़, के समक्ष,

ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) सुरिंदर सिंह, एसएम, वीएसएम - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य- प्रतिवादी

2013 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3249

फ़रवरी 22, 2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226, 227 - सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007- धारा 4, 27 और 34 - याचिकाकर्ता को भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था और जांच अदालत द्वारा दोषी पाए जाने के बाद उसे सेना से हटा दिया गया था - याचिकाकर्ता ने अपने निष्कासन के आदेश के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और कारगिल प्रकरण में वरिष्ठ कमांडरों की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग की - उक्त याचिका को ट्रिब्यूनल (रेस्प नंबर 2) में स्थानांतरित कर दिया गया था। उक्त अधिनियम की सहायता से इसकी धारा 34 के गठन के बाद - याचिकाकर्ता ने पक्षपात की आशंका के आधार पर मामले को स्थानांतरित करने की मांग की क्योंकि उसे प्रशासनिक सदस्य पर मूल जांच अदालत के सदस्यों में से एक का मित्र होने का संदेह था जिसने उसे दोषी पाया - अधिनियम की धारा 27 के तहत सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष के समक्ष याचिकाकर्ता का आवेदन भी खारिज कर दिया गया था - इसलिए, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह याचिका - यह निर्धारित करने के लिए बिंदु यह है कि क्या न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए पक्षपात की आशंका के आरोपों के लिए न्यायिक समीक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए - आयोजित, नहीं - रिट याचिका खारिज कर दी गई।

यह माना जाता है कि इसे दूसरे शब्दों में कहें तो यह देखा गया कि परीक्षण यह होगा कि क्या सभी तथ्यों से पूरी तरह अवगत एक उचित बुद्धिमान व्यक्ति को पूर्वाग्रह की गंभीर आशंका होगी। गैर-आर्थिक पूर्वाग्रह के मामलों में, "वास्तविक संभावना" परीक्षण को उचित संदेह पर प्राथमिकता दी गई है और न्यायालयों ने लगातार माना है कि पूर्वाग्रह के प्रश्न को तय करने में मानवीय संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना होगा।

(पैरा 19)

आगे कहा गया, इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में इस न्यायालय के सीमित अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और ट्रिब्यूनल द्वारा मामले को स्थानांतरित नहीं करने के निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए; इसके अलावा, तथ्य यह है कि पक्षपात की कोई वास्तविक संभावना नहीं है और केवल एक उचित संदेह का आरोप लगाया गया है और मानवीय संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, यह तथ्यों और परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

(पैरा 28)

याचिका खारिज

श्री सुदर्शन गोयल, अधिवक्ता, सुश्री रंजीता गिल, अधिवक्ता और श्री एमपी गोस्वामी, याचिकाकर्ता के वकील।

श्री गुरप्रीत सिंह, अधिवक्ता, भारत संघ के वरिष्ठ पैनल वकील

S.S. SARON, J.

(1) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस याचिका के माध्यम से सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ क्षेत्रीय पीठ चंडीमंदिर (संक्षेप में - "ट्रिब्यूनल") (प्रतिवादी नंबर 2) द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2012 (अनुलग्नक पी -13) और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 10.1.2013 (अनुलग्नक पी -15) के आदेश को रद्द करने की मांग की है। नई दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच जिसके तहत याचिकाकर्ता की ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) की बेंच से उसके मामले को स्थानांतरित करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ सदस्य हैं।

(2) याचिकाकर्ता को 15.3.1970 को भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने हमेशा आरोही कैरियर ग्राफ को बनाए रखा, सक्रिय संचालन/युद्ध में दो बार घायल हुए और घाव पदक के प्राप्तकर्ता हैं। उनके पास एक मेधावी और प्रतिष्ठित सेना सेवा है और उन्हें वीरता के लिए सेना पदक, वशिष्ठ सेवा पदक, दो बार घाव पदक और सेना प्रमुख द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। अपनी सेवा के दौरान, उन्हें 18.6.1998 को ब्रिगेडियर के रूप में पदोन्नत किया गया था और उन्हें कमांडर 121 (स्वतंत्र) इन्फैंट्री ब्रिगेड समूह के रूप में तैनात किया गया था जिसे 'कारगिल ब्रिगेड' के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र के विस्तृत विश्लेषण और सराहना के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि उसने सेना प्रमुख सहित वरिष्ठ कमांडरों को क्षेत्र की भेद्यता और कारगिल में दुश्मन के खतरे को बढ़ाने के बारे में सूचित और जानकारी दी। उन्होंने अतिरिक्त संसाधनों, सैनिकों की मांग की और मौजूदा रक्षा की प्राथमिकताओं की समीक्षा के लिए प्रस्ताव भेजा। इनमें कारगिल में शीतकालीन हवाई निगरानी, शीतकालीन डाक सेवाओं और हताहतों को निकालने के लिए कारगिल में एयर ऑपरेशन हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने के अलावा अतिरिक्त संसाधनों और सैनिकों की मांग शामिल थी। हालांकि, इन्हें 3 इन्फैंट्री डिवीजन द्वारा ठुकरा दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, कारगिल सेक्टर में दुश्मनों के बढ़े खतरे की धारणा पर उसके द्वारा भेजी गई रिपोर्टों (संलग्नक पी-1 से पी-4) पर गंभीरता से ध्यान देने और चुनौती का सामना करने की तैयारी करने के बजाय, वरिष्ठ कमांडरों ने कारगिल सेक्टर में सेना की रक्षात्मक भूमिका से असंबद्ध गतिविधियों को अधिक महत्व दिया, जैसे लेह में चिड़ियाघर का निर्माण। यह प्रस्तुत किया गया है कि लड़ने वाले सैनिकों को जंगली जानवरों और पक्षियों को पकड़ने के लिए तैनात किया गया था। इसके अलावा, रक्षा संसाधनों का उपयोग जानवरों और पक्षियों के लिए पिंजरे बनाने और उनके परिवहन, भोजन और रखरखाव के लिए किया जाता था। कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ और जब युद्ध चल रहा था, याचिकाकर्ता को जून 1999 में ब्रिगेड की कमान से हटा दिया गया था और उसे विभिन्न संरचनाओं में तैनात किया गया था। दिनांक 06.08.1999 को उन परिस्थितियों की जांच के लिए एक जांच अदालत बुलाई गई थी जिनके तहत दिनांक 25.8.1998 के पत्र की विषय-वस्तु; 121 (आई) इन्फैंट्री ब्रिगेड समूह द्वारा उत्पन्न "ब्रीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ" और किसी भी अन्य वर्गीकृत दस्तावेज अनधिकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि 70 इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह, जो खुद अत्यधिक गोपनीय दस्तावेजों की सामग्री को लीक करने के दोषी थे, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के सदस्यों में से एक थे, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ अपनी रिपोर्ट दी थी। याचिकाकर्ता को 29.5.2001 को भारत सरकार द्वारा पेंशन और ग्रेच्युटी के साथ तत्काल प्रभाव से सेना से हटा दिया गया था। याचिकाकर्ता को हटाने के आदेश में, दो अन्य आरोपों के अलावा, छह आरोप थे, जैसा कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी द्वारा दर्ज निष्कर्षों के आधार पर उल्लेख किया गया है, जिसके ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह सदस्य थे।

(3) याचिकाकर्ता ने सेना सेवा से हटाने के आदेश के खिलाफ और कारगिल प्रकरण में वरिष्ठ कमांडरों की भूमिका की स्वतंत्र जांच के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका (यानी 2002 की सीडब्ल्यूपी संख्या 4786) दायर की। उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और इस बीच, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 55) ("अधिनियम" - संक्षेप में) पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, सेना कामकों के सभी लंबित मामलों को इसकी धारा 4 के अंतर्गत गठित सशस्त्र सेना अधिकरण को अंतरित कर दिया गया था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाकर्ता की रिट याचिका को ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) को स्थानांतरित कर दिया गया और 2010 का टीए नंबर 273 सौंपा गया। ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2), यह प्रस्तुत किया गया है, याचिकाकर्ता की रिट याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय से ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) में स्थानांतरित करते समय दो बेंच बैठे थे क्योंकि ट्रिब्यूनल के दो न्यायिक सदस्य और चार प्रशासनिक सदस्य (प्रतिवादी नंबर 2) थे। 2010 के टीए संख्या 273 के रूप में दिल्ली से रिट याचिका के हस्तांतरण पर, याचिकाकर्ता का मामला 13.7.2010 को एक बेंच के समक्ष तय किया गया था जिसमें माननीय श्री न्यायमूर्ति एनपी गुप्ता (सेवानिवृत्त) न्यायिक सदस्य के रूप में और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एएस बहिया प्रशासनिक सदस्य के रूप में शामिल थे। इसके बाद, अन्य प्रशासनिक सदस्य माननीय न्यायमूर्ति एन.पी.गुप्ता के साथ उनके स्थानांतरण तक अलग-अलग तारीखों पर बैठे रहे हैं। गुप्ता के स्थानांतरण के बाद, विभिन्न प्रशासनिक सदस्य माननीय श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजेश चंद्रा के साथ बैठे हैं, जो 2012 में ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) में शामिल हुए थे। उन पीठों के विवरण का उल्लेख किया गया है जहां याचिकाकर्ता का मामला विभिन्न तारीखों पर तय किया गया था।

(4) यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ को तब तक नहीं जानता था जब तक कि वह ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह की बेटी की शादी में उनसे नहीं मिला था। याचिकाकर्ता को उक्त विवाह के लिए आमंत्रित किया गया था और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बरार भी उसी में शामिल हुए थे। ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एन. एस. बरार को अपने करीबी दोस्त के रूप में पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एन.एस. बराड़ ने अपनी करीबी दोस्ती से इनकार नहीं किया और रेजिमेंटल एसोसिएशन के मजबूत बंधन पर जोर दिया और कहा कि वे दोनों एक ही रेजिमेंट से थे।

(5) यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के मामले की किसी भी तारीख पर प्रभावी सुनवाई नहीं हुई थी, जब याचिकाकर्ता का मामला उस बेंच के समक्ष आया था, जिसके लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बरार सदस्य थे। कार्यवाही के विवरण का उल्लेख किया गया है जो इसे प्रस्तुत किया गया है जो नियमित सुनवाई थी। न तो मुख्य मामले और न ही विविध आवेदनों पर मेरिट के आधार पर सुनवाई की गई या सुनवाई के दौरान उस बेंच द्वारा फैसला किया गया, जिसके लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एन.एस. यह प्रस्तुत किया गया है कि 29.10.2012 को जब "वर्गीकृत दस्तावेजों का वर्गीकरण और संचालन, 1966" पुस्तिका उपलब्ध कराने के लिए विविध आवेदन (2011 का एमए संख्या 105) का मामला सुना जा रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य याचिकाकर्ता के वकील को अपनी दलीलें पूरी करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। यह आरोप लगाया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य के उक्त व्यवहार ने याचिकाकर्ता के मन में भय और आशंका पैदा कर दी कि माननीय प्रशासनिक सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ की ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह, जिनके साथ याचिकाकर्ता के हितों का टकराव है, की पीठ से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सुनवाई नहीं होगी और न ही न्याय, जिसकी पीठ लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस ने कहा था। बराड़ सदस्य हैं। उक्त भय और आशंका के कारण, याचिकाकर्ता ने अपने वकील को मौखिक रूप से ट्रिब्यूनल की किसी अन्य बेंच (प्रतिवादी नंबर 2) को अपने मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध करने का निर्देश दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य सदस्य नहीं थे। याचिकाकर्ता के निर्देश पर वकील ने तदनुसार मामले के हस्तांतरण के लिए ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) के समक्ष अनुरोध किया। ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) ने 10.12.2012 के लिए अपना निर्णय सुरक्षित रखा और उक्त तारीख को आक्षेपित आदेश (अनुबंध पी -13) के तहत याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

(6) दिनांक 10.12.2012 (अनुलग्नक पी-13) के आदेश के खिलाफ, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 27 के तहत दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष के समक्ष एक आवेदन (अनुलग्नक पी -14) दायर किया कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के करीबी दोस्त थे और बाद में याचिकाकर्ता के साथ हितों का टकराव है और वह [ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह] न्यायालय के सदस्य थे (घ) सरकार ने याचिकाकर्ता को वर्गीकृत दस्तावेजों को लीक करने के लिए दोषी ठहराते हुए जांच की जांच शुरू कर दी है। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के निष्कर्ष दिनांक 29.5.2001 (अनुबंध पी-7) के आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख आधारों में से एक थे, जो ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी संख्या 2) के समक्ष चुनौती का विषय है। यह प्रस्तुत किया गया था कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के साथ घनिष्ठ मित्रता और रेजिमेंटल एसोसिएशन ने याचिकाकर्ता के मन में उचित विश्वास पैदा किया कि उक्त घनिष्ठ मित्रता ने लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य के मन में याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा किया था जो इस तथ्य से प्रकट हुआ था कि 29.11.2012 को, उक्त माननीय सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ याचिकाकर्ता के वकील को अपनी दलीलें पूरी करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। इसने याचिकाकर्ता को अपने वकील को ट्रिब्यूनल की दूसरी पीठ (प्रतिवादी नंबर 2) को मामले को स्थानांतरित करने का निर्देश देने के लिए प्रेरित किया था, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य नहीं थे। आवेदन (अनुलग्नक पी -14) नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए तय किया गया था और इसे 10.1.2013 (अनुबंध पी -15) को आदेश के साथ खारिज कर दिया गया था; "सुना है। इस मामले को क्षेत्रीय पीठ, चंडीगढ़ से दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं है। वर्तमान आवेदन तदनुसार खारिज किया जाता है। उक्त आदेश को वर्तमान याचिका में भी शामिल किया गया है।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.1.2013 (अनुलग्नक पी -15) एक गैर-बोलने वाला आदेश है। आवेदन दिनांक 9.1.2013 (अनुलग्नक पी-14) में लिए गए आधारों पर चर्चा नहीं की गई है और न ही याचिकाकर्ता के मामले को ट्रिब्यूनल की दूसरी पीठ (प्रतिवादी नंबर 2) को स्थानांतरित करने के आवेदन को खारिज करने का कोई कारण बताया गया है, जिसके लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एन.एस. बराड़ सदस्य नहीं हैं। माननीय अधिकरण ने आवेदन में उल्लिखित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार नहीं किया है और न ही इसके साथ संलग्न किया है और न ही उक्त निर्णय का पालन न करने के किसी कारण का उल्लेख किया है। यह तर्क दिया गया है कि ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के करीबी दोस्त हैं और बाद में अनधिकृत व्यक्तियों को वर्गीकृत दस्तावेजों की सामग्री को लीक करने और उपलब्ध कराने में याचिकाकर्ता की भूमिका और जिम्मेदारी पर विचार करने के लिए गठित कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के सदस्य थे। उक्त कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने निष्कर्ष दिए जो 29.5.2001 को याचिकाकर्ता को सेना से हटाने के कारणों में से एक था जिसे ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) के समक्ष चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता और ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के बीच वर्गीकृत दस्तावेजों की सामग्री को अनधिकृत व्यक्तियों को लीक करने के लिए हितों का टकराव होने के कारण, यह प्रस्तुत किया जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य के लिए इस मामले की सुनवाई करना अनुचित होगा क्योंकि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ पक्षपाती हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी, जिसके ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह एक सदस्य थे, ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अपनी खोज और राय दी थी, बिना जांच पूरी किए उसे वर्गीकृत दस्तावेजों को लीक करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह खुद सबसे संवेदनशील और उच्च वर्गीकृत दस्तावेजों की सामग्री को बनाए रखने और लीक करने का दोषी रहा है और याचिकाकर्ता को गलत तरीके से उक्त आरोप का दोषी ठहराया गया है। मनोहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली के लिए मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अशोक कल्याण वर्मा द्वारा प्रकाशित अजय कुमार जैन द्वारा प्रकाशित पुस्तक "कारगिल : ब्लड ऑन द स्नो" के अंशों का संदर्भ दिया गया है। उद्धृत किए गए उद्धरण के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह फरवरी 2001 में आयोजित एक बैठक के दौरान लेखक को ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह, कमांडर 70 ब्रिगेड द्वारा प्रदान किए गए विवरण पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने विविध आवेदन (2010 का एमए संख्या 152) में अन्य दस्तावेजों के साथ 121 (स्वतंत्र) इन्फैंट्री ब्रिगेड समूह से संबंधित 'कार्रवाई के बाद की रिपोर्ट' पेश करने की मांग की थी, जिसके जवाब में प्रतिवादियों ने विशेषाधिकार का दावा

किया था। इसलिए, याचिकाकर्ता के अनुसार यह स्पष्ट था कि जिन प्रतिवादियों ने इसे गोपनीय और उच्च वर्गीकृत होने का दावा करते हुए संरचनाओं/इकाइयों की 'कार्रवाई रिपोर्ट के बाद' पेश करने के लिए विशेषाधिकार का दावा किया था, उसी की सामग्री ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह द्वारा 1999 से 2001 के बीच एक अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई थी। इस प्रकार, वर्गीकृत दस्तावेजों के लीक होने के मुद्दे पर याचिकाकर्ता और ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के बीच हितों का गंभीर टकराव था। याचिकाकर्ता के ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के साथ हितों के टकराव का एक और उदाहरण उस क्षेत्र के संबंध में है जहां बड़ी घुसपैठ हुई थी। याचिकाकर्ता ने उसी विविध आवेदन (2010 का एमए नंबर 152) द्वारा मुख्यालय 3 इन्फैंट्री डिवीजन सिग्नल नंबर 0-2015 दिनांक 20.4.1999 के उत्पादन की मांग की और जिसके लिए विशेषाधिकार का दावा किया गया है। उक्त संकेत, यह प्रस्तुत किया गया है, यह दर्शाता है कि जिस क्षेत्र में बड़ी घुसपैठ हुई थी, वह ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह की कमान में था और घुसपैठ के समय याचिकाकर्ता की कमान में नहीं था। इससे याचिकाकर्ता से घुसपैठ की जिम्मेदारी ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह पर स्थानांतरित होने की संभावना है। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के मित्र होने के नाते, यह प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से मामले की सराहना और निर्णय लेने की संभावना नहीं है। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय के सिद्धांत के अनुसार प्रशासनिक सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ को उस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए जिसमें याचिकाकर्ता और लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बरार के करीबी मित्र ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के हित में टकराव हो। याचिकाकर्ता के इस विश्वास की पुष्टि 29.11.2012 को हुई जब लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य याचिकाकर्ता के वकील को अपनी दलीलें पूरी करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि एक न्यायिक सदस्य है और ट्रिब्यूनल के तीन प्रशासनिक सदस्य (प्रतिवादी नंबर 2) हैं और मामले को आसानी से ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) की बेंच में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें से लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य सदस्य नहीं हैं।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील पीके घोष, आईएएस बनाम जेजी राजपूत, (1995) 6 एससीसी 744 के मामले पर मजबूत भरोसा करते हैं, जिसमें यह माना गया है कि एक वादी के लिए यह उम्मीद करना अनुचित नहीं माना जा सकता है कि उसके मामले को किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए। यदि कोई बाध्यकारी आवश्यकता नहीं है, जैसे कि विकल्प की अनुपस्थिति, तो यह उचित है कि न्यायाधीश को मामले की सुनवाई करने वाली बेंच से खुद को अलग कर लेना चाहिए। न्यायाधीश द्वारा यह कदम उठाया जाना आवश्यक है, इसलिए नहीं कि वह किसी भी तरह से न्याय करने में प्रभावित होने की संभावना है, बल्कि इसलिए कि मामले की सुनवाई से वादी के मन में एक उचित आशंका पैदा होने की संभावना है कि न्यायाधीश का दिमाग अवचेतन रूप से हो सकता है, निर्णय लेने में कुछ बाहरी कारक से प्रभावित किया गया है, खासकर अगर यह विपरीत पार्टी के पक्ष में होता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के मन में एक उचित भय और आशंका है कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ द्वारा मामले की सुनवाई में, उसे उचित उपचार नहीं मिलेगा।

(9) जवाब में, श्री गुरप्रीत सिंह, अधिवक्ता, भारत संघ के वरिष्ठ पैनल वकील ने प्रस्तुत किया है कि वह विभिन्न तिथियों पर ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) के समक्ष उपस्थित थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता वास्तव में मामले में देरी करने के उद्देश्य से प्रत्येक सुनवाई पर अनावश्यक और अनुचित स्थगन ले रहा है। सुनवाई की प्रत्येक तारीख पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले की सुनवाई को स्थगित करने के लिए कुछ बहाना उठाया जाता है। वर्तमान याचिका केवल मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक चाल के रूप में दायर की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ के खिलाफ पक्षपात के आरोप बाद में विचार किए गए हैं और मामले की सुनवाई में और देरी करने के लिए उठाए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के पास सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत गठित ट्रिब्यूनल के एक आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और इस तरह के ट्रिब्यूनल पर उच्च न्यायालय को अधीक्षण की शक्तियां प्रदान करने के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 (4) द्वारा बनाई गई एक विशिष्ट रोक है। इसलिए, उच्च न्यायालय के पास ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित मामलों को स्थानांतरित करने की कोई शक्ति नहीं है।

(10) हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों पर विचारशील विचार किया है। जहां तक इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने 15165 फ्लाइट लेफ्टिनेंट ओंकार सिंह बावा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 15165 फ्लाइट लेफ्टिनेंट ओंकार सिंह बावा बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एक याचिका दायर की थी। भारत संघ और अन्य, 2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 6927 का निर्णय 25.1.2013 को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार देखा गया: "हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इस तरह के आदेश के खिलाफ वैधानिक अपील सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 30 के तहत प्रदान की गई है, हालांकि, "एल चंद्र कुमार आदि बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के संबंध में। (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्नल एडी नरगोलकर बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में एआईआर 1997 एससी 1125 और 2009 की सीडब्ल्यूपी सं 13360 में दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में कर्नल एडी नरगोलकर बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश में यह निर्णय लिया था कि भारत संघ और अन्य, एआईआर 1997 एससी 1125 और दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 13360 में कर्नल एडी नरगोलकर बनाम भारत संघ और अन्य के रूप में भी 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 13360 में यह निर्णय दिया था। इसी अधिनियम के संदर्भ में उपर्युक्त निर्णयों का अनुसरण करते हुए हम इस याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। तदनुसार, हमने रिट याचिका के गुण-दोष के आधार पर पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है।

(11) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के पास सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। एल. चन्द्र कुमार आदि में वि. भारत संघ और अन्य, एआईआर 1997 एससी 1125 यह माना गया था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक बुनियादी और अनिवार्य विशेषता है। मोटे तौर पर, यह माना गया था कि भारत में न्यायिक समीक्षा में तीन पहलू शामिल हैं; i) विधायी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा, ii) न्यायिक निर्णय की न्यायिक समीक्षा और iii) प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा। उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों को संविधान को बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है और इस उद्देश्य से इसकी व्याख्या करने की शक्ति प्रदान की गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान द्वारा परिकल्पित शक्ति संतुलन बना रहे और विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों के निर्वहन में संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण न करें। इसलिए, एल चंद्र कुमार के मामले (सुप्रा) में निर्णय के अनुसार इस न्यायालय के पास ट्रिब्यूनल के न्यायिक निर्णयों के संबंध में न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, हालांकि, संविधान के अनुच्छेद 227 (4) के मद्देनजर इसके प्रशासनिक कामकाज के संबंध में अधीक्षण की कोई शक्ति नहीं होगी, जो निम्नानुसार है: -

> "इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां प्रदान करने वाली नहीं समझी जाएगी।

(12) इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 ट्रिब्यूनल सशस्त्र बलों का ट्रिब्यूनल होने के नाते, इस न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित निर्णयों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का सीमित अधिकार क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में बनाम समर कुमार सरकार, (2009) 15 एससीसी 444 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त अधीक्षण की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त शक्ति के रूप में व्यापक नहीं है। आमतौर पर, यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है, अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, केवल यह विचार करने के लिए कि क्या न्यायालय या ट्रिब्यूनल के निर्णय में क्षेत्राधिकार की त्रुटि है, जो इसके अधीक्षण के अधीन है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक त्रुटि को सुधार सकता है, लेकिन वह अनुच्छेद 227 के तहत, ट्रिब्यूनल से एक मामले को वापस नहीं ले सकता है और उसी का निपटारा नहीं कर सकता है। यह देखा गया कि यह उचित होता यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करके प्रशासनिक न्यायाधिकरण को मामले को अपने पास

स्थानांतरित करने के बजाय मामले को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश देता। उक्त मामला एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से संबंधित मामला था, जिस पर संविधान के अनुच्छेद 227 (4) की कठोरता लागू नहीं होती है, जबकि यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के मामले में लागू होता है। इसलिए, जहां तक ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) के प्रशासन पर अधीक्षण का संबंध है, इस न्यायालय के पास वस्तुतः कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसका सीमित अधिकार क्षेत्र इसके द्वारा पारित निर्णयों की न्यायिक समीक्षा तक फैला हुआ है।

(13) दिनांक 10.12.2012 (अनुलग्नक पी-13) के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) द्वारा यह देखा गया है कि मामले को 29.11.2012 को सुनवाई के लिए लिया गया था और विविध आवेदनों पर प्रतिद्वंद्वी तर्कों को काफी समय तक सुना गया था। इसके बाद, दलीलों को दोपहर के सत्र में सुनवाई के लिए टाल दिया गया। दोपहर के सत्र के लिए इकट्ठा होने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मामले की सुनवाई पर कुछ आपत्तियां उठाईं, जिसकी पीठ लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ इस आधार पर सदस्य थे कि मामले में उनकी रुचि का टकराव था और वह दिसंबर 2009 में ब्रिगेडियर देविंदर सिंह की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। ब्रिगेडियर देविंदर सिंह कारगिल संघर्ष के दौरान बटालिक सेक्टर में ब्रिगेड कमांडर भी थे और उन्हें अपने ब्रिगेड सेक्टर में घुसपैठ और संघर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन के लिए दोषी ठहराया गया था। तदनुसार, मामले को किसी अन्य पीठ को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया था। हालांकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह केवल मामले की सुनवाई से बचने के लिए एक चाल थी क्योंकि यह बहस के लिए तैयार था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिश्तेदारों, दोस्तों, सहयोगियों और परिचितों के रिश्तेदारों की शादियों में भाग लेना सामाजिक दायित्वों का एक हिस्सा है और ट्रिब्यूनल के माननीय सदस्य यह देखने में विफल रहे कि उनमें से एक, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस बराड़ (सेवानिवृत्त) ब्रिगेडियर देविंदर सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने के बाद मामले को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने का आधार हो सकता है। आगे यह देखा गया कि कारगिल संघर्ष में उनकी भूमिका से संबंधित ब्रिगेडियर देविंदर सिंह के मामले का फैसला मई 2010 में ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ द्वारा उनके पक्ष में किया गया था। इन परिस्थितियों में, माननीय सदस्य फिर से याचिकाकर्ता के लिए किसी भी हित के टकराव को देखने में विफल रहे। रिकॉर्ड से यह भी देखा गया कि इस मामले की सुनवाई एक अन्य बेंच द्वारा की गई थी जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बरार 17.1.2011, 07.3.2011, 8.7.2011 और 9.12.2011 को सदस्यों में से एक थे। उन तारीखों पर और उक्त तिथि अर्थात 10.12.2012 तक कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए, मामले को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं मिला और तदनुसार प्रार्थना खारिज कर दी गई। तथापि, यह पाया गया कि यदि याचिकाकर्ता ऐसा महसूस करता है तो वह 10012013 तक मामले के ऐसे अंतरण की मांग करने के लिए सशस्त्र बल अधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष आवेदन कर सकता है।

(14) याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 27 के संदर्भ में एक आवेदन (अनुलग्नक पी -14) दायर किया, जिसमें चंडीगढ़ में ट्रिब्यूनल की किसी अन्य पीठ को अपने मामले को स्थानांतरित करने की मांग की गई, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ सदस्य नहीं थे। अधिनियम की धारा 27 सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को मामलों को एक बेंच से दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करती है। वही निम्नानुसार पढ़ता है: -

> "27. मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ को अंतरित करने की अध्यक्ष की शक्ति - किसी पक्षकार के आवेदन पर और संबंधित पक्षकारों को नोटिस दिए जाने के पश्चात् और उनकी सुनवाई की ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह सुनना चाहता है या

ऐसी सूचना के बिना अपने प्रस्ताव पर अध्यक्ष एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटान के लिए अंतरित कर सकेगा, किसी अन्य बेंच को।

(15) सशस्त्र बल अधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष ने एक प्रशासनिक सदस्य के साथ दिनांक 10.01.2013 (अनुबंध पी-15) के आक्षेपित आदेश के तहत मामले को ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) से दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं पाया। तदनुसार स्थानांतरण आवेदन खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश को हालांकि प्रशासनिक रूप में कहा जा सकता है, फिर भी एक अर्ध-न्यायिक आदेश है और यह कहा जा सकता है कि उक्त आदेश पारित करते समय अध्यक्ष ने अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण की विशेषताओं वाले अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी के रूप में कार्य किया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के निर्णयों के संबंध में न्यायिक समीक्षा के सीमित अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि तथ्य यह है कि अध्यक्ष ने कारणों को दर्ज नहीं किया है, तथ्यों और परिस्थितियों में बहुत अधिक परिणाम नहीं है क्योंकि नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के एक अन्य सदस्य के साथ अध्यक्ष ने 10.12.2012 के आदेश (अनुलग्नक पी -13) का समर्थन किया है। चंडीमंदिर में ट्रिब्यूनल की क्षेत्रीय पीठ, जिसमें मामले को ट्रिब्यूनल की किसी अन्य बेंच को स्थानांतरित नहीं करने के कारण हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ सदस्य नहीं हैं। इसलिए, नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.1.2013 (अनुलग्नक पी-15), जिसे इस याचिका में लगाया गया है, जिसके तहत मामले को क्षेत्रीय पीठ चंडीगढ़ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं पाया गया और तदनुसार स्थानांतरण आवेदन को खारिज कर दिया गया, इसे केवल एक प्रशासनिक आदेश भी कहा जा सकता है जो ट्रिब्यूनल की किस बेंच को इसकी सुनवाई करनी है। हालांकि, पक्षपात के आरोपों पर निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा जो संविधान के अनुच्छेद 226 के संदर्भ में सीमित अधिकार क्षेत्र का होगा।

(16) संविधान के अनुच्छेद 22 बी के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जौहरी मल, (2004) 4 एससीसी 714 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 में निहित उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का दायरा और सीमा मामले से मामले में भिन्न होगी, आदेश की प्रकृति, संगत संविधि और लोक प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति सहित अन्य संगत कारक, अर्थात् क्या शक्ति सांविधिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उद्देश्य पर्यवेक्षी भूमिका ग्रहण करना या सर्वव्यापी के वस्त्र धारण करना नहीं है। शक्ति का उद्देश्य न तो कानून के शासन के तहत शासन की समीक्षा करना है और न ही अदालतें उन क्षेत्रों में कदम रखती हैं जो विशेष रूप से राज्य के अन्य अंगों के लिए सर्वोच्च लेक्स द्वारा आरक्षित हैं। निर्णय और कार्य जिनके पास न्यायिक स्वभाव नहीं है, न्यायिक समीक्षा अदालत के समक्ष विचार के लिए सख्ती से नहीं गिर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा, संक्षेप में कहें, है:

(1) अदालतें, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रशासनिक निकायों के निर्णयों पर अपील में नहीं बैठती हैं।

(2) न्यायिक समीक्षा के लिए एक याचिका केवल कुछ अच्छी तरह से परिभाषित आधारों पर होगी।

(3) एक प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश जो इसमें निहित विवेक का प्रयोग करता है, न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि विवेक का प्रयोग स्वयं विकृत या अवैध है।

(4) बिना किसी और चीज के महज गलत फैसला न्यायिक समीक्षा की शक्ति को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है; एक अदालत को प्रदान किया गया पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार यह देखने तक सीमित है कि ट्रिब्यूनल अपने अधिकार की सीमा के भीतर कार्य करता है और इसके फैसले न्याय की हत्या का अवसर नहीं देते हैं.

(5) अदालतों को सरकारी कर्तव्यों और कार्यों को करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय आमतौर पर राज्य के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक न्यायाधीश के सामाजिक और आर्थिक विश्वास को विधायी निकायों के निर्णय के विकल्प के रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए। (देखें इरा मुन बनाम इलिनोइस राज्य, 94 यूएस 113)।

(17) इसलिए, इस न्यायालय के सीमित अधिकार क्षेत्र की सीमा को देखते हुए, ट्रिब्यूनल के सदस्यों में से एक लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ के खिलाफ पक्षपात के आरोप पर विचार किया जाना है। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ जिस बेंच के सदस्य हैं, से मामले के हस्तांतरण की मांग करने वाले पक्षपात का आरोप इस आधार पर लगाया गया है कि याचिकाकर्ता का ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के साथ हितों का टकराव है और ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ का उनके साथ घनिष्ठ संबंध और मित्रता है। यह कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष विविध आवेदनों में से एक की सुनवाई के दौरान, ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ याचिकाकर्ता के वकील को दलीलें पूरी करने की अनुमति नहीं दे रहे थे और उनके उक्त व्यवहार ने याचिकाकर्ता के मन में भय और आशंका पैदा कर दी थी कि उन्हें लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट की बेंच से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सुनवाई और न्याय नहीं मिलेगा। जनरल (सेवानिवृत्त) एन.एस. बराड़ इसके सदस्य थे। इसी डर और आशंका के कारण याचिकाकर्ता ने अपने वकील को निर्देश दिया कि वह अपने मामले को ट्रिब्यूनल की किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित करने के लिए मौखिक रूप से अनुरोध करे, जिसके बारे में कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़, प्रशासनिक सदस्य सदस्य नहीं थे। ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) द्वारा दिनांक 10.12.2012 (अनुबंध पी 13) के आक्षेपित आदेश के तहत प्रार्थना को खारिज कर दिया गया है।

(18) पक्षपात के आरोप के संबंध में यह देखा जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण बनाम केडी बाली, एआईआर 1988 एससी 1099 में कहा था कि पक्षपात का गठन करने के लिए पक्षकार के मन में पूर्वाग्रह की आशंका का औचित्य होना चाहिए। प्रशासन की पवित्रता के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही के लिए पार्टी को यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि प्राधिकरण पक्षपाती है और पार्टी के खिलाफ निर्णय लेने की संभावना है। लेकिन यह एक पार्टी द्वारा महसूस किया गया हर संदेह नहीं है जो इस निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए कि कार्यवाही की सुनवाई करने वाला प्राधिकारी पक्षपाती है। आशंका का आकलन स्वस्थ, उचित और औसत दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, न कि किसी सनकी व्यक्ति की आशंका के आधार पर।

(19) में डॉ. जी. सरना वी. (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले पर विचार किया जहां उक्त मामले में अपीलकर्ता ने मानव विज्ञान के प्रोफेसर के पद पर उपस्थित होने और असफल होने के बाद उसमें प्रतिवादी संख्या 8 के चयन के विरुद्ध पक्षपात का आरोप लगाया। यह आरोप लगाया गया था कि उक्त चयनित उम्मीदवार के चयन समिति के दो विशेषज्ञों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। यह देखा गया कि ऐसे मामले में जो देखा जाना चाहिए जहां प्रशासनिक बोर्ड या निकाय के सदस्य के संबंध में पूर्वाग्रह का आरोप लगाया गया है, क्या यह मानने के लिए एक उचित आधार है कि उसके पक्षपाती होने की संभावना थी; दूसरे शब्दों में, क्या पीड़ित पक्ष के खिलाफ सदस्य के मन में पक्षपात की पर्याप्त संभावना है। पूर्वाग्रह के प्रश्न का निर्णय करते समय, मानवीय संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(20) ए.के. क्रैपक भारत संघ और अन्य, एआईआर 1970 एससी 150 चयन बोर्ड का एक सदस्य स्वयं चयन के लिए एक उम्मीदवार था, हालांकि उसने अपने चयन के समय बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया था, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों के चयन करते समय पूरे समय भाग लिया था। ऐसे सदस्य के हित और कर्तव्य के बीच टकराव था और पक्षपात

की उचित संभावना थी। बोर्ड द्वारा तैयार की गई चयन सूची को दूषित माना गया। यह माना गया कि असली सवाल यह नहीं है कि चयन बोर्ड का सदस्य अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते समय या अर्ध-न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते समय पक्षपातपूर्ण था, क्योंकि किसी व्यक्ति की मनःस्थिति को साबित करना मुश्किल है। इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या यह मानने के लिए कोई उचित आधार है कि उनके पक्षपाती होने की संभावना थी। पूर्वाग्रह के प्रश्न का निर्णय करते समय, मानवीय संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(21) पीडी दिनाकरन बनाम न्यायाधीश जांच समिति, (2011) 8 एससीसी 380 में उक्त मामले में याचिकाकर्ता न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 (2) के तहत राज्यों की परिषद (राज्य सभा) के अध्यक्ष द्वारा गठित समिति में सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता को शामिल करने से व्यथित था। समिति के जिस सदस्य के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया गया था, उसने बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भाग लिया था और याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने का विरोध करते हुए भाषण दिया था और उसके खिलाफ प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। पक्षपात के आरोप के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ यह देखा गया था कि किसी व्यक्ति को लिस की विषय-वस्तु में हित के आधार पर निर्णय लेने से अयोग्य घोषित करने के लिए, पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना का परीक्षण लागू किया जाना है। दूसरे शब्दों में, किसी को यह जांचना होगा कि क्या उस व्यक्ति की ओर से पूर्वाग्रह का वास्तविक खतरा है जिसके खिलाफ इस तरह की आशंका इस अर्थ में व्यक्त की जाती है कि वह किसी पार्टी का पक्ष ले सकता है या उसका विरोध कर सकता है। प्रत्येक मामले में, न्यायालय को यह विचार करना होगा कि क्या एक निष्पक्ष और सूचित व्यक्ति, सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, यथोचित रूप से यह आशंका करेगा कि न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यह देखा गया कि परीक्षण यह होगा कि क्या सभी तथ्यों से पूरी तरह अवगत एक यथोचित बुद्धिमान व्यक्ति को पूर्वाग्रह की गंभीर आशंका होगी। गैर-आर्थिक पूर्वाग्रह के मामलों में, "वास्तविक संभावना" परीक्षण को "उचित संदेह" परीक्षण पर प्राथमिकता दी गई है और न्यायालयों ने लगातार माना है कि पूर्वाग्रह के प्रश्न को तय करने में मानव संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना होगा। यह जोड़ा गया था कि पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना न केवल शिकायत करने वाले पक्ष द्वारा निर्धारित सामग्री से प्रकट होनी चाहिए, बल्कि ऐसे अन्य तथ्यों से भी दिखाई देनी चाहिए, जिन्हें उचित पूछताछ करके आसानी से पता लगाया जा सकता था और आसानी से सत्यापित किया जा सकता था।

(22) इसलिए, 'उचित संदेह' परीक्षण के खिलाफ, 'वास्तविक संभावना' की कसौटी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसे देखा जाना चाहिए; इसके अलावा, मानवीय संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को उक्त संदर्भ में ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या रिकॉर्ड पर सामग्री और अन्य उपस्थित परिस्थितियां हैं जो यह मानती हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ मामले को तय करने में निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करेंगे। केवल इस आशंका पर कि ट्रिब्यूनल के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ ने ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह की बेटी की शादी में भाग लिया था, जिसके साथ याचिकाकर्ता पर हितों का टकराव है और उक्त सदस्य के बारे में कहा जाता है कि उसका करीबी रेजिमेंटल संबंध है और दोस्ती अपने आप में यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि उक्त सदस्य निष्पक्ष या तर्कसंगतता के साथ कार्य नहीं करेगा। शादियों, एक दोस्त और सहयोगी के सामाजिक कार्यों में भाग लेना, जिसके साथ याचिकाकर्ता को हितों का टकराव कहा जाता है और जिसमें याचिकाकर्ता स्वयं भी मौजूद था, अपने आप में ऐसी परिस्थिति नहीं कहा जा सकता है कि न्यायिक निर्णय अनुचित या अन्यायपूर्ण होगा। यह अधिक से अधिक एक संदेह मात्र होगा। याचिकाकर्ता यह दिखाने के लिए उत्तरदायी है कि मामले का फैसला लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़

द्वारा किए जाने की स्थिति में पक्षपात की वास्तविक संभावना है और केवल संदेह की आशंका नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना का मामला नहीं बनाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेजिमेंटल एसोसिएट और ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के मित्र होने के नाते संबंधित प्रशासनिक सदस्य याचिकाकर्ता के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे।

(23) में चंद्र कुमार चोपड़ा वी। भारत संघ, (2012) 6 एससीसी 369 अपीलकर्ता सेना में मेजर था। उनके खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों के लिए उनके खिलाफ एक जनरल कोर्ट मार्शल बुलाया गया था। कोर्ट मार्शल के विचारण की शुरुआत में, उक्त अपीलकर्ता ने कोर्ट मार्शल की संरचना के सदस्य होने वाले कुछ अधिकारियों पर इस आरोप पर आपत्ति जताई कि उसने उप-क्षेत्र के कमांडर के खिलाफ कुछ अनियमितताओं के संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष सेना अधिनियम 1950 की धारा 27 के तहत एक वैधानिक शिकायत दर्ज की थी और सभी पीठासीन अधिकारी ने संयोजक अधिकारी के अधीन काम किया था। अर्थात्, ब्रिगेडियर फूलका। इसलिए, कोर्ट मार्शल की संरचना, यह आरोप लगाया गया था, दूषित था। पीठासीन अधिकारी और कोर्ट मार्शल के अन्य सदस्यों ने सेना अधिनियम 1950 की धारा 130 और सेना नियम 1954 के नियम 44 का विज्ञापन किया और अंततः आपत्ति को रद्द कर दिया और मुकदमे के साथ आगे बढ़े। एक पूर्ण सुनवाई के बाद, कोर्ट मार्शल ने पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप साबित हो गए थे और तदनुसार उसे सजा सुनाई गई थी। पक्षपात के आरोप के संबंध में, यह देखा गया कि ब्रिगेडियर जेएस फुल्का ने सेना अधिनियम की धारा 109 के तहत कोर्ट मार्शल बुलाया था। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत वैधानिक शिकायत कमांडर 71, सब-एरिया द्वारा की गई कुछ अनियमितताओं से संबंधित थी। यह देखा गया कि कोर्ट मार्शल में, जैसे ही न्यायालय की बैठक हुई, इसने अभियुक्त को पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के नाम पढ़े और यह पूछताछ की गई कि क्या उन्हें उक्त मामले में ट्रिब्यूनल के किसी सदस्य के पक्ष में होने पर कोई आपत्ति है। उक्त मामले में अपीलकर्ता ने मूल रूप से वैधानिक शिकायत दर्ज करने के आधार पर ट्रिब्यूनल की संरचना पर आपत्ति जताई। जिस प्रश्न पर विचार किया गया था वह यह था कि क्या संबंधित उप-क्षेत्र के कमांडिंग अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में की गई शिकायत ट्रिब्यूनल की संरचना को केवल इस आधार पर पक्षपातपूर्ण मंच के रूप में करेगी कि सभी सदस्य उक्त उप-क्षेत्र में काम करते हैं। पहले के मामले के कानून पर विचार करने के बाद यह माना गया था कि यह स्पष्ट है कि केवल संदेह या आशंका पूर्वाग्रह की दलील पर विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह किसी की कल्पना का पहलू नहीं हो सकता। यह एक उचित व्यक्ति के विवेक के अनुरूप होना चाहिए। रिकॉर्ड पर लाई गई परिस्थितियां दिखाती हैं कि यह एक उचित व्यक्ति के दिमाग में एक धारणा पैदा कर सकता है कि पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना है। यह नहीं भूलना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक राजनीति में, अपनी वैचारिक घटना और अंतर्निहित सर्वोत्कृष्ट रूप से न्याय सुशासन का आधार है। यह माना गया कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में जो कानून के शासन द्वारा शासित होती है, कार्रवाई की निष्पक्षता, औचित्य, तर्कसंगतता, संस्थागत निर्दोषता और गैर-पक्षपाती न्याय वितरण प्रणाली उन स्तंभों का गठन करती है जिन पर इसका अस्तित्व निरंतरता में रहता है। किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के सदस्य के गैर-पक्षपाती रवैये की आवश्यकता से जुड़ी पवित्रता के बावजूद, और इस सिद्धांत के बावजूद कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि देखा जाना चाहिए, इसकी जांच रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री के आधार पर की जानी चाहिए कि क्या कोई जंगली बना रहा है, एक मुकदमे या पूर्वाग्रह के आरोप को विफल करने के लिए अप्रासंगिक और काल्पनिक आरोप एक उचित व्यक्ति की सोच के अनुरूप है जो पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना की कसौटी पर खरा उतर सकता है। सिद्धांत को निर्वात में आकर्षित नहीं किया जा सकता है। उक्त मामले में संयोजक अधिकारी कमांडर नहीं रह गया था। कमांडर, संयोजक अधिकारी के बारे में अनियमितताओं के विरुद्ध एक सामान्य शिकायत थी। उक्त मामले में कोर्ट मार्शल में अपीलकर्ता द्वारा जो आपत्ति की गई थी, वह यह थी कि उसकी शिकायत केंद्र सरकार के पास लंबित थी। रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं लाया गया था कि कोर्ट मार्शल का गठन करने वाले किसी भी सदस्य के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत था। इस प्रकार, प्राप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, यह

धारण करना बेहद मुश्किल था कि पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना थी क्योंकि उचित आदमी की समझदारी इतनी कल्पना नहीं कर सकती है और एक सही दिमाग वाला व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के इसे त्याग देगा। अपीलकर्ता की ओर से इस संबंध में उठाए गए सबमिशन को रद्द कर दिया गया था।

(24) वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता के हितों का टकराव ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के साथ कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एन. एस. बराड़ ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह से वरिष्ठ हैं। वह अब उसी रेजिमेंट में नहीं हैं और दोनों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके अलावा, यह समझना मुश्किल है कि लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बरार ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक सदस्य के रूप में सशस्त्र बलों से निपटने वाले ऐसे ट्रिब्यूनल के अपने अर्ध-न्यायिक कार्य के निर्वहन में काम करते हुए याचिकाकर्ता के पूर्वाग्रह के प्रति पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे और वह भी इस आधार पर कि याचिकाकर्ता का ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) देविंदर सिंह के साथ हितों का टकराव है।

(25) अशोक कुमार यादव व अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, एआईआर 1987 एससी 454 यह माना गया था कि यदि चयन समिति का एक सदस्य जो योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करने के प्रयोजनों के लिए गठित किया गया है और सदस्यों में से एक चयन के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार से निकटता से संबंधित है, तो ऐसे सदस्य के लिए केवल उससे संबंधित उम्मीदवार के साक्षात्कार में भाग लेने से पीछे हटना पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन उसे पूरी चयन प्रक्रिया से पूरी तरह से हट जाना चाहिए और अधिकारियों से चयन समिति में उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने के लिए कहना चाहिए क्योंकि अन्यथा चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रह की उचित संभावना के कारण किया गया सभी चयन दूषित हो जाएगा। हालांकि, उक्त सिद्धांत जिसके लिए आवश्यक है कि चयन समिति का एक सदस्य, जिसका करीबी रिश्तेदार चयन के लिए उपस्थित हो रहा है, को चयन समिति का सदस्य बनने से इनकार कर देना चाहिए या अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को छोड़ देना चाहिए, यह माना गया था, लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरण के मामले में लागू होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह केंद्र हो या राज्य। इसलिए, संवैधानिक प्राधिकारियों और उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए, समिति के किसी सदस्य द्वारा चयन प्रक्रिया में पूर्ण वापसी का सिद्धांत, जब उसका रिश्तेदार उपस्थित हो रहा था, को अनुपयुक्त माना गया था। ट्रिब्यूनल के गठन (प्रतिवादी नंबर 2) में उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं जो एक संवैधानिक पदाधिकारी और एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। इसलिए, ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) का गठन करने वाले सदस्यों के उच्च पदों और रैंकों को ध्यान में रखते हुए, यह संभावना नहीं है कि पक्षपात की कोई संभावना है या उस मामले के लिए पूर्वाग्रह का संदेह भी है। तथ्यों और परिस्थितियों में हमें यह मानने का कोई कारण नहीं मिलता है कि प्रशासनिक सदस्य जिसके खिलाफ पूर्वाग्रह का आरोप लगाया गया है, वह याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने पर अन्यायपूर्ण या अनुचित कार्य करेगा। इन परिस्थितियों में, केवल संदेह के आधार पर ट्रिब्यूनल की क्षेत्रीय बेंच और प्रिंसिपल बेंच द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करना पूरी तरह से अनुचित होगा, जिसमें मामले को उस बेंच से स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया गया था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बरार सदस्य हैं।

(26) डॉ. जी. सरना (सुप्रा) बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय (सुप्रा) पूर्वाग्रह की तर्कसंगतता या पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना के सवाल पर विचार नहीं किया गया क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि उक्त मामले में अपीलकर्ता सभी प्रासंगिक तथ्यों को जानता था, उसने साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले या साक्षात्कार के समय चयन समिति के गठन के खिलाफ थोड़ी उंगली भी नहीं उठाई। ऐसा लगता है कि वह स्वेच्छा से चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और इससे अनुकूल सिफारिश लेने का मौका लिया। इसलिए, ऐसा करने के बाद, यह माना गया कि यह उनके लिए खुला नहीं था कि जब निर्णय प्रतिकूल था तो समिति के गठन पर सवाल उठाए।

माणक लाल बनाम डॉ. प्रेम चंद सिंघवी, एआईआर 1957 एससी 425 पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि कार्यवाही पर पहले चरण में एक ही दलील लेने में अपीलकर्ता की विफलता ने उसके खिलाफ छूट का एक प्रभावी अवरोध पैदा किया। इसलिए, छूट का सिद्धांत लागू किया गया था। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल (प्रतिवादी नंबर 2) के समक्ष पेश हुआ था, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ सदस्य थे। रिकॉर्ड के आधार पर ट्रिब्यूनल द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.12.2012 (अनुलग्नक पी-13) में यह देखा गया है कि इस मामले की सुनवाई अन्य पीठों द्वारा की गई थी जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएसबरार 17.1.2011, 7.3.2011, 8.7.2011 और 9.12.2011 को सदस्यों में से एक थे और आक्षेपित आदेश की तारीख तक उन तारीखों पर कोई आपत्ति नहीं थी। इससे कम से कम आंशिक छूट का निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्योंकि विद्वान न्यायाधीशों के बयानों को इसके समक्ष कार्यवाही के तरीके के रूप में पूर्ण सत्य और निर्णायक माना जाना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि उन तारीखों पर कुछ भी ठोस नहीं हुआ था और यह 29.11.2012 को सुनवाई के दौरान है जब लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ प्रशासनिक सदस्य अपने वकील को दलीलें पूरी करने की अनुमति नहीं दे रहे थे कि उक्त आचरण ने याचिकाकर्ता को अपने वकील को मामले को स्थानांतरित करने का निर्देश देने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में यह उचित रूप से देखा जा सकता है कि सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश अपने विचारों और विचारों को व्यक्त करते हैं जो वे रख सकते हैं और कभी-कभी काफी दृढ़ता से भी। हालांकि, इसका मतलब हमेशा यह नहीं होगा कि न्यायाधीश ने अपना विचार व्यक्त किया है पक्षपातपूर्ण है या उसने मामले को पूर्वनिर्धारित किया है। वास्तव में, किसी मामले की प्रभावी सुनवाई के लिए और अस्पष्टता के एक बिंदु को दूर करने के लिए, कभी-कभी एक काउंटर व्यू पॉइंट रखना वांछनीय होता है ताकि उसी के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सके। इसका किसी भी कारण से यह अर्थ नहीं होगा कि पीठासीन अधिकारी या न्यायाधीश का इस मामले में हित है। एक वादी, जो इस तरह के आधार पर आशंका पैदा करता है, उसे तर्कसंगतता के साथ ऐसा करने वाला नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में यह अक्सर देखा जाता है कि एक न्यायाधीश के पास बहस करने वाले वकील की प्रस्तुतियों और मामले की बारीकी से जांच करने पर जो विचार हो सकता है या माना जा सकता है, वह काफी गलत माना जाता है। हालांकि, ऐसे मामले में जहां सुनवाई के दौरान एक न्यायाधीश एक वकील को अपनी प्रस्तुतियाँ करने की अनुमति नहीं देता है, अनावश्यक रूप से अपने तर्कों के प्रवाह को बाधित करता है या किसी महत्वपूर्ण विशेष मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं देता है, तो अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि न्यायाधीश का पूर्वाग्रह था। केवल इसलिए कि ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एनएस बराड़ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सवाल उठाए हैं या याचिकाकर्ता के वकील को दलीलों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास पूर्वाग्रह है और उन्हें मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, वादी को अधिकरण के किसी विशेष सदस्य से अपने मामले के अंतरण की मांग करने अथवा उक्त सदस्य को पक्षपात के मात्र निराधार आरोपों के आधार पर मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करने के लिए कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्रिब्यूनल के एक सदस्य को खुद को अलग करने के लिए कहना या पूर्वाग्रह के आरोपों पर किसी मामले के हस्तांतरण का आदेश देना न्याय के बड़े प्रशासनिक हित की सेवा नहीं करेगा क्योंकि यह एक वादी को ट्रिब्यूनल की एक विशेष पीठ से बचने की अनुमति देगा और यहां तक कि अंततः अपनी पसंद के न्यायाधीश को सुरक्षित करने के लिए आगे बढ़ेगा। इसलिए, अधिकरण का कोई न्यायाधीश या सदस्य केवल पक्षपात के आरोपों के आधार पर किसी मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसमें सार की कमी है।

(27) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पीके घोष, आईएएस बनाम जेजी राजपूत (सुप्रा) के मामले का उल्लेख किया है। हालांकि, उक्त मामले का अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा। उक्त मामले में प्रतिवादी अहमदाबाद नगर निगम का कर्मचारी था। उन्होंने

अपने निलंबन को चुनौती देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें उनका प्रतिनिधित्व एक वकील ने किया जिसे बाद में गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उक्त प्रतिवादी ने अपने निलंबन पर रोक लगा दी और उसके बाद उसके वकील को, जिसने उसका प्रतिनिधित्व किया था, गुजरात उच्च न्यायालय की पीठ में पदोन्नत कर दिया गया। प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व तब एक अन्य वकील द्वारा किया गया था। अहमदाबाद नगर निगम और प्रतिवादी के बीच उच्च न्यायालय में एक समझौता हुआ। उच्च न्यायालय द्वारा विशेष सिविल आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी गई थी। अहमदाबाद नगर निगम का मामला यह था कि निपटान के संदर्भ में, प्रतिवादी को एक विशेष पैमाने पर सेवा में पुष्टि की गई थी और उसे एक आवासीय क्वार्टर आवंटित किया गया था। इसके बाद, उक्त प्रतिवादी ने अंतिम आदेश की समीक्षा के लिए एक सिविल विविध आवेदन दायर किया जो उसी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया जिसने विशेष सिविल विविध आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी थी। उनकी संतुष्टि पर समीक्षा आवेदन खारिज कर दिया गया कि नगर निगम द्वारा समझौते के नियमों और शर्तों का पालन किया गया था। प्रतिवादी को तब कुछ नगरपालिका संपत्ति की चोरी के लिए आरोप-पत्र दिया गया था। नगर निगम के अनुसार, उक्त आरोप पत्र पहले के विवाद से जुड़ा नहीं था। हालांकि, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक और सिविल विविध आवेदन दायर किया जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि उक्त आरोप पत्र के अनुसरण में जांच पर रोक लगाई जाए और अपीलकर्ता जो अहमदाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त थे, उन्हें अदालत की अवमानना के लिए दंडित किया जाए। इसके अलावा, पहले विशेष आवेदन को बहाल किया जाए। इस आवेदन को उसी पीठ ने खारिज कर दिया था जिसने पहले इस मामले का निपटारा किया था। प्रतिवादी ने यह स्वीकार नहीं किया कि विशेष सिविल विविध आवेदन में विवाद समाप्त हो गया था और उसने न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत अवमानना याचिका दायर की थी। यह अवमानना याचिका एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई जिसमें उनके पूर्व वकील, जिन्होंने उनका प्रतिनिधित्व किया था और पदोन्नत किए गए थे, एक सदस्य थे। यह देखा गया कि न्यायाधीश, जो बेंच में थे, पहले उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में उपस्थित हुए थे, जिस पर अवमानना याचिका में न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाया गया था। इसलिए, उक्त तथ्यों और अवमानना याचिका में प्रतिवादी के विशिष्ट मामले को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि इन परिस्थितियों में विद्वान न्यायाधीश के लिए उचित रास्ता प्रतिवादी द्वारा उठाए गए रुख के कारण अवमानना मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना था, जिसके लिए वह विशेष सिविल आवेदन में एक वकील के रूप में पेश हुआ था और नगर निगम द्वारा की गई आपत्तियों के बावजूद अवमानना याचिका की सुनवाई उसी पीठ ने की थी। उक्त परिस्थितियां वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है जहां ट्रिब्यूनल के सदस्य ने पहले याचिकाकर्ता या किसी ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया था जिसके साथ हितों का टकराव हो सकता है।

(28) इसलिए, न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय के सीमित अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और ट्रिब्यूनल द्वारा मामले को स्थानांतरित नहीं करने के निर्णय को भी ध्यान में रखते हुए; इसके अलावा, तथ्य यह है कि पक्षपात की कोई वास्तविक संभावना नहीं है और केवल एक उचित संदेह का आरोप लगाया गया है और मानवीय संभावनाओं और मानव आचरण के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, यह तथ्यों और परिस्थितियों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

(29) तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

<u>अस्वीकरण :</u>

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा